activity to the needs of society. Coupled with this is the comprehensive review of the public administration of the country done by the Administrative Reforms Commission and this has thrown up a number of fresh ideas on how the administrative system should be streamlined. Government have already aken decisions on a number of recommendations of the Administrative Reforms Commission. These and other changes which will be initiated as a result of a continuous review of the adminis rative arrangements will lead to significant changes in the pa tern of administration

S.T.D. Scheme between Gandhinagar and Ahmedabad

1132. SHRI K. S. CHAVDA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether advance action for planning add ordering the equipment for direct dialling between Gandhinagar and Ahmedabad had been taken in 1968 ; and

(b) if so, the time Government will take to commission the above Subscribers Trunk Dialling Scheme ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H N. BAHUGUNA) : (a) Yes sir, advance action for planning direct dialling between Gandhinagar and Ahmedabad was started in 1968.

(b) It is hoped that this Scheme will be commissioned by 1973

Bad Telephone Service by Sonari Exchange, Assam

1133. SHRI BISWANARAYAN SHASTRI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether he is aware that the subscribers of Telephone in Sonari Exchange, Assam had disconnected their phones as a mark of protest against (i) continuous bad service, (ii) wrong and inflated Telephone Bills, (iii) non-response to the complaints ; and

(b) if so, the steps he proposes to take in this matter ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) Enquiries made do not reveal what is suggested in this part of the question. Some telephones at Sonari were recently disconnected by the Department due to non-payment of outstanding bills

(b) Does not arise.

मध्य प्रदेश के जाओरा डाकघर में पर्याप्त सुविधाओं की कमी

1134. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में जाओरा स्थित डाकखाने में, जो निम्न ग्रेड के अन्तर्गत आता है, न तो पर्याप्त संख्या में कर्मचारी है और न ही वहां अन्य सुविधायें उपलब्ध है ;

(ख) उक्त ग्रेड के डाकखानों में कितने कर्मचारियों को नियुक्त करने की मंजूरी दी जाती है और स्वीकृत संख्या के अनुसार कर्मचारियों को नियुक्त न करने के क्या कारण है ,

(ग) उक्त डाकखाने में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों के न होने के परिणामस्वरूप साधारण जनता को प्रतिदिन कुप्रबन्ध और कार्य में विलम्ब होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ; और

(घ) उक्त डाकखाने में पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) (क) जी नहीं ।

(ख) जाओरा निम्नचयन ग्रेड उप डाकघर के लिए मंजूर किए गए कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :

निम्नचयन ग्रेड नायब पोस्टमास्टर

क्लर्क

अतिरिक्त विभागीय डाक टिकट-विक्रेता	1
प्रधान डाकिया	1
मेल ओवरसियर	1
डाकिये तथा ग्राम डाकिये	7+1
संदेशवाहक	2
मेल पियन	3
अतिरिक्त विभागीय संदेश वाहक	1
अतिरिक्त विभागीय चौकीदार	1
अंशकालिक धोबी	1
अंशकालिक झाड़ूवाला	1

मंजूर किए गये सभी पद भरे हुए है ।

(ग) प्रश्न ही नही उठता । जनता से कुप्रबन्ध या विलम्ब की कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) प्रश्न ही नही उठता ।

मध्य प्रदेश में आयात लाइसेंस कार्यालय

1135. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडे** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन राज्यों के नाम क्या है जहां आयात लाइसेंस कार्यालय स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश मे ऐसा कोई कार्यालय नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो क्या मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य मे आयात और निर्यात के उप-मुख्य नियंत्रक का एक कार्यालय खोलने का मंत्रालय से अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबध मे क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) एक विवरण जिसमे विभिन्न राज्यों मे स्थित लाइसेंस कार्यालयों के नाम और पते तथा उनका क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र दर्शाया गया है सभा पटल पर रखा गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या LT 285/71]** ये लाइसेंस कार्यालय अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित आयातकों से संबंधित लाइसेंसों हेतु आवेदन पत्रों पर, ऐसे मामलों को छोड़कर जहां लाइसेंस देने के कार्य का केन्द्रीयकरण कर दिया है, कार्यवाही करते है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) मामला विचाराधीन है ।

Review *Re.* Continued Posting of C.R.P. and Army Units in West Bengal

1136. SHRI TRIDIB CHAUDHURI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the question of the continued posting of C.R.P and Army units in West Bengal in order to assist the West Bengal Government to maintain law and order in the State has been reviewed by her Ministry and the new democratic Coalition Government in the state after assumption of power by the latter Government on April 2, 1971 ,

(b) whether any request has been received by Government from the State Government of West Bengal for withdrawing the C.R.P. and the Army from the State and for keeping them at convenient points outside the State so as to be available in case of any emergency ; and